Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 336 रायपुर, बुधवार 31 दिसम्बर 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

राज्य सरकार के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 31 जनवरी तक देनी होगी अपनी अचल संपत्ति की जानकारी

महानदी भवन से जारी हुआ आदेश

रायपुर, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। राज्य सरकार के तमाम अधिकारी-कर्मचारी को 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अपनी अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव को तीन बिंदुओं में निर्देश जारी किया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवकों को अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य बताया है. जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों के कैलेण्डर वर्ष 1.1.2025 से 31.12.2025 तक की स्थिति में धारित किए वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा.

राज्य पुलिस सेवा के 16 अधिकारियों को नए साल में मिला प्रमोशन, आदेश जारी

रायपुर, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुशंसा पर और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वर्ष के अंतिम दिन एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है. छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधिकारियों के हित में यह निर्णय लिया गया है, जिसे पुलिस महकमे में उत्साहवर्धक कदम माना जा रहा है. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति एवं छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त 16 अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी या समतुल्य रैंक के पद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी या समतुल्य रैंक के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया है. पदोन्नत अधिकारियों में रितेश चौधरी, जितेन्द्र कुमार खूंटे, मती अंजली नाग (गुप्ता), कर्ण कुमार उके, मनोज कुमार ध्रुव, पुष्पेन्द्र नायक, मनोज तिर्की, मती सारिका वैद्य, सु निधि नाग, कपिल चन्द्रा, अविनाश कुमार मिश्रा, ईश्वर प्रसाद त्रिवेदी, योगेश कुमार साहू, मयंक तिवारी, सु रश्मीत कौर चांवला तथा अनिल कुमार विश्वकर्मा शामिल हैं.

साय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले

पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से, ऑटो एक्स-पो के दौरान रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट

रायपुर, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद की बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय किये जाने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति (गारंटी) पर लिए गए ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण राशि वापस करने का अनुमोदन किया गया। ये राष्ट्रीय निगम हैं- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम। वर्तमान में इन ऋणों पर राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। ऋण की पूरी अदायगी होने पर यह ब्याज व्यय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय निगमों से एनओसी (अदेय प्रमाण पत्र) प्राप्त होने पर शासन की ओर से दी गई 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य शासन पर वित्तीय बोझ कम होगा और भविष्य में होने वाले अनावश्यक व्यय से बचत सुनिश्चित होगी।

मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रू. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर की गई 40 रू. प्रति क्विंटल किया है। सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 03 माह की जगह न्यूनतम 02 माह की मिलिंग करनी होगी। मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लिया। इससे नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में विसंगतियां दूर होंगी। इन संशोधनों से राज्य में निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी, स्थायी रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी, जिससे मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा, इस संबंध में निर्देशित किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

ब्रेकिंग न्यूज

खालिदा जिया को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब, भारत सहित कई देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर (न्यूज चैनल)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख रहीं बेगम खालिदा जिया को बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर ढाका स्थित उनके गुलशन आवास 'फिरोज़ा' लाया गया, जहां परिवारजनों, करीबी रिश्तेदारों और पार्टी नेताओं ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के अवसर पर ढाका में शोक और श्रद्धा का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और तीन दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। खालिदा जिया की नमाज़-ए-जनाज़ा आज दोपहर 2 बजे ढाका के माणिक मिया एवेन्यू स्थित राष्ट्रीय संसद भवन के दक्षिणी प्रांगण में अदा की जाएगी। जनाज़े में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके बाद उन्हें शेर-ए-बांग्ला नगर में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के मकबरे के पास दफनाया जाएगा।

2025 के अंतिम दिवस भूपेश बघेल पहुंचे अमरकंटक

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। गौरव जैन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल के अंतिम दिन अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना किया. बीती शाम को वो जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के दौरे पर थे. जहां वो कांग्रेस जिलाअध्यक्ष के शपथ ग्रहण में हुए थे. बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मां नर्मदा से प्रदेश की खुशहाली की कामना किया है. उन्होंने अपने पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अमरकंटक में अपने निर्मल जल से कंकर-कंकर को भी शंकर बनाने वाली जीवनदायिनी मां नर्मदा के पवित्र दर्शन कर, बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की. इस दौरान कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, हस्ड्र प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय, जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही अध्यक्ष गजमती भानु भी सीएम के साथ मौजूद थे.

चूहा- सुनती हो, 2025 की विदाई आखिर कैसे की जाए..!
चुहिया- हां जी, पुराने बुरे किए का कुछ तो पश्चाताप होना चाहिए..!

अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत

रायपुर, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। नेशनल हाईवे-53 पर मंगलवार की देर शाम दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा लखौली ओवरब्रिज पर देर शाम 7 बजे हुआ, जब बाइक च्ड 04-4714 में सवार 2 युवक आरंग से रायपुर की ओर जा रहे थे तभी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान संदीप निषाद (18 वर्ष) निवासी बड़गांव (तुमगांव) तथा तिलक निषाद (20 वर्ष) निवासी रायतुम (पटेवा) के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवरब्रिज पर अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ा, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक घिसटते हुए करीब 50 मीटर दूर जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही आरंग थाना प्रभारी हरीश साहू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

10वीं-12वीं कक्षा की कल से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू

अनुपस्थिति पर नहीं मिलेगा दोबारा मौका

रायपुर, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है. बाह्य परीक्षकों की उपस्थिति में होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा इस बार 20 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही है. इसके कारण ही प्रैक्टिकल परीक्षा भी 10 दिन पहले होगी. मंडल ने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 1 से 20 जनवरी की तिथि तय की है.

हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य अपनी सुविधा के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेंगे. प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए माशिमं ने पहले ही गाइड लाइन जारी की है. जिसके अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है. होगी. इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की अनुपस्थित विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में विशेष अनुमति नहीं मिलेगी और न ही दोबारा अवसर दिया जाएगा. प्रैक्टिकल परीक्षा माशिमं द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में संपन्न होगी. स्कूल अपनी मर्जी से बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकते.

प्रैक्टिकल परीक्षा का आकस्मिक निरीक्षण

मंडल के अधिकारी प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान आकस्मिक निरीक्षण करेंगे. ऐसे में प्रैक्टिकल परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए संपन्न कराने निर्देशित किया गया है. प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु गत वर्षों की बची हुई उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा. कमी होने पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करने कहा गया है. पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए विद्यार्थियों के प्रायोगिक अंक मंडल द्वारा अमान्य किए जाएंगे.

राशन कार्ड धारकों के फिंगरप्रिंट फेल होने पर चेहरा प्रमाणीकरण सहित स्वीकृत विकल्प से होगा ई-केवायसी

राशन दुकानों को सूची तैयार करने के निर्देश

रायपुर, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत जिन राशन कार्ड सदस्यों का फिंगरप्रिंट काम नहीं करने के कारण ई-केवायसी नहीं हो पा रहा है, ऐसे सदस्यों की सूची तैयार की जा रही है. इस सूची के आधार पर इन सदस्यों को चेहरा प्रमाणीकरण सहित अन्य स्वीकृत विकल्प के जरिए उनका ई-केवायसी किया जाएगा. जिला प्रशासन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया. इस आदेश के तहत अब सभी सार्वजनिक वितरण दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन सदस्यों का केवायसी फिंगरप्रिंट के कारण नहीं हो पा रहा है, उसकी सूची तैयार करें.

3.36 लाख सदस्यों का केवायसी होना बाकी

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 22 लाख 4 हजार 430 राशनकार्ड धारी सदस्यों में से 18 लाख 67 हजार 768 सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है, जबकि अभी भी 3 लाख 36 हजार 662 सदस्यों का ई-केवायसी होना शेष है. इन सदस्यों में ऐसे हजारों सदस्य हैं, जिनका फिंगरप्रिंट काम नहीं करने के कारण उनका केवायसी नहीं हो पा रहा है. ऐसे सदस्यों में ज्यादातर वृद्ध एवं 3 से 5 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं. इसके अलावा दिव्यांग तथा कठिन परिश्रम के कारण उंगलियों के फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहे हैं. ऐसे भी कई सदस्य है, जो अब तक केवायसी नहीं करा पार हैं.

मोबाइल एप के सर्वर में दिक्कत

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी राशनकार्डधारी परिवारों के प्रत्येक सदस्य का आधार आधारित ई-केवायसी कराना अनिवार्य है. इसके लिए मोबाइल एप भी बनाए गए हैं, लेकिन इस एप के सर्वर में दिक्कत होने के कारण भी कई सदस्य केवायसी नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि अफसरों का कहना है कि कभी-कभी सर्वर की समस्या रहती होगी, लेकिन एप के माध्यम से सदस्य घर बैठे आसानी से अपना केवायसी कर सकता है. इसके बाद भी अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो राशन दुकान या विभागीय कार्यालय में आकर इसकी जानकारी दे सकते हैं, जिसका निराकरण किया जाएगा.

राशन दुकानों में एप के माध्यम से कराया जा रहा केवायसी

खाद्य विभाग ने छूटे हुए सदस्यों का केवायसी कराने के लिए सभी राशन दुकानों को निर्देश दिए हैं. इसके तहत इन दुकानों में छूटे हुए हितग्राहियों का मशीन के साथ मोबाइल एप के माध्यम से भी केवायसी किया जा रहा है.

आमरण अनशन के बीच डीएड अभ्यर्थियों ने खून से लिखा पत्र, सरकार पर मौन होने का आरोप

उग्र आंदोलन की तैयारी

- आमरण अनशन पर बैठे लोगों का कहना है, सरकार को संवेदनशील होकर उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए
- हाईकोर्ट का आदेश, फिर भी सरकार बेपरवाह

रायपुर, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों का दर्द अब शब्दों से आगे निकल चुका है. सालों की पढ़ाई, प्रशिक्षण और अदालतों में चली लंबी लड़ाई के बाद भी जब सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, तब बेरोज़गार युवाओं ने इंसानियत को झकझोर देने वाला कदम उठाया है. आमरण अनशन पर बैठे ह्र.श्वस्र अभ्यर्थियों ने खून से पत्र लिखकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मदद की गुहार लगाई है. आमरण अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि सरकार को संवेदनशील होकर उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए.

धरना स्थल पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों ने खून से लिखे पत्रों के ज़रिये बताया कि कैसे उनका भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि जब ज्ञापन, प्रदर्शन और अदालत के आदेश भी सरकार को नहीं जगा सके, तब उन्होने अपनी पीड़ा खून से लिखी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि यह पत्र नहीं, बल्कि टूटती उम्मीदों की चीख है. आमरण अनशन पर अभ्यर्थी, कहा-नौकरी दो या जान ले लो। रायपुर के माना-तूता धरना स्थल पर 24 दिसंबर से बेरोज़गार डीएड,बीएड अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं. ठिठुरती सर्दी और भूख से बेहाल ये लोग लगातार आमरण अनशन पर डटे हैं. इनका कहना है कि चाहे जो भी हो उनकी मांगें जबतक पूरी नहीं होती वो अनशन खत्म नहीं करेंगे. अभ्यर्थियों ने शासन से जल्द से जल्द मांग पूरी करने की मिन्नत भी की है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि रिक्त पदों पर 2 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

अभ्यर्थियों ने बताया कि आज भी लगभग 2300 पद खाली हैं बावजूद इसके हजारों प्रशिक्षित युवा बेरोज़गारी का दंश झेलने को मजबूर हैं. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. अभ्यर्थियों का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि उनकी मांगें सिर्फ नौकरी और सम्मानजनक जीवन के लिए है. अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने गंभीर और मानवीय संकट के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान या पहल सामने नहीं आई है. अभ्यर्थियों का कहना है कि संवाद और निर्णय के अभाव ने हालात को विस्फोटक बना दिया है.छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों का यह आंदोलन अब सिर्फ भर्ती का मुद्दा नहीं रहा. खून से लिखा गया पत्र, आमरण अनशन और नौकरी दो या जान ले लो। जैसे नारे सरकार के सामने सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं. अभ्यर्थियों के साथ अब लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या युवाओं की ज़िंदगी से बड़ा कोई और एजेंडा है?

युवा संवाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन, पर्यावरण, नशा और अकेलेपन पर जताई चिंता

रायपुर, 31 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने युवा संवाद कार्यक्रम में विकास, पर्यावरण और युवाओं के भविष्य पर अपनी बात कही. उन्होंने अरावली पर्वतमाला का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया अब तक ऐसा विकास मॉडल नहीं बना पाई है, जिसमें पर्यावरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर साथ साथ बिना नुकसान के चल सकें, इसलिए अब संतुलित विकल्प तलाशना ही होगा. बता दें कि सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं. इस दौरान आज रायपुर एम्स में वे युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए युवाओं से रू-ब-रू हो रहे हैं. भागवत ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ से चेताया कि अंधाधुंध विकास की दौड़ अगर इसी तरह चलती रही तो आने वाली पीढ़ियां पर्यावरणीय संतुलन की भारी कीमत चुकाएंगी. उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रकृति दोनों का समानांतर विकास जरूरी है, इसके लिए नीतियों और जीवनशैली दोनों में बदलाव लाना होगा. इसके साथ उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रोजगार और करियर के साथ साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी भी समझें और अपने छोटे छोटे फैसलों से बड़ी सकारात्मक शुरुआत करें. डॉ. भागवत ने युवाओं में बढ़ते नशे को गंभीर चिंता बताते हुए कहा कि आज का यूथ अंदर से लोनली फील कर रहा है. परिवारों में संवाद घटने और रिश्तों के न्यूट्रल होते जाने की वजह से युवाओं के सामने मोबाइल और नशा आसान विकल्प की तरह खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर फैमिली के भीतर बात चीत और इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा तो बाहर की बुरी आदतों की खींच कम हो जाएगी. समाज और परिवार, दोनों को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें युवा अकेलेपन से भागकर नशे में नहीं, बल्कि सार्थक कामों में अपना समय लगाएं.